

है, उसको रोका जाए। मध्य प्रदेश में पिछले 10 वर्षों में कमी पलायन नहीं हुआ था, लेकिन अब हो रहा है, जो कि बहुत ही निंदनीय है और हम सबके लिए यह अच्छा नहीं है, इसलिए इस पर भी विचार करना चाहिए।

SHRIMATI KANTAKARDAM (Uttar Pradesh): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Navaneethakrishnan. You have to make out your case. You should not take the name of the other State and unnecessarily make allegations. Otherwise, हंगामा होगा।

**Intervention required in construction of
Mekedatu dam by Karnataka**

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (Tamil Nadu): Sir, I am not naming anybody. In the Cauvery issue, the hon. Supreme Court has modified the Tribunal Order and water allocations have been made, but the Supreme Court has held that this arrangement may be enforced for 15 years. But now, Karnataka is making attempts to construct a dam at Mekedatu. They have already conducted the DPR. The Tamil Nadu Government opposed it. They have now applied for environmental clearance. Now, clearance cannot be granted illegally. Legally, dams cannot be constructed there without the consent of Tamil Nadu. Tamil Nadu is strongly opposing it. Hence, Sir, I would very humbly urge the hon. Prime Minister to intervene and see to it that no clearance is given to Karnataka Government. This is my humble pray because now Tamil Nadu is water deficit. That is well known. Cauvery water is very important for crop cultivation. The farmers are suffering. Hence, again and again, in all humbleness, I urge the hon. Prime Minister to intervene in this matter immediately, and environmental clearance should not be granted to the State of Karnataka.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Ravi Prakash Verma.(Interruptions)... No, no. Nothing shall go on record.(Interruptions)... Mr. Hariprasad, you are a senior Member. Please sit down. This is not the way.(Interruptions)... This is not the way. Please sit down.(Interruptions)... Don't complicate the issue. You know how the system works. We also know... (Interruptions)... That is why I cautioned him too. Now, Shri Ravi Prakash Verma.

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. R. LAKSHMANAN (Tamil Nadu): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI K.R. ARJUNAN (Tamil Nadu): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI A.K. SELVARAJ (Tamil Nadu): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI S. MUTHUKARUPPAN (Tamil Nadu): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI R.S. BHARATHI (Tamil Nadu): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

Problems arising due to stray animals

श्री रवि प्रकाश वर्मा (उत्तर प्रदेश): सर, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर खींचना चाहता हूँ।

सर, पूरे उत्तर प्रदेश में और मेरा अनुमान है कि पूरे उत्तर भारत में बहुत बड़ी तादाद में गोवंशीय पशु आवारा घूम रहे हैं, जिनको ऐसे ही छोड़ दिया गया है। सरकार द्वारा इसमें कोई सुनिश्चित पॉजिटिव पॉलिसी न बना पाने के कारण ही ऐसा सामने आ रहा है। ये जो जानवर हैं, इनकी तादाद बहुत ज्यादा है और अब ये मुझे आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश में इन जानवरों के द्वारा अब तक, एक साल में सैकड़ों लोग मारे गए हैं। ये पशु खेतों और घरों में घुस कर हमला करते हैं। कई मामलों में देखा गया है कि ये हाईवेज़ ब्लॉक कर देते हैं, जिस वजह से वहां पर एक्सीडेंट हो रहे हैं और लोगों की जानें जा रही हैं।

महोदय, यह बड़ी अजीब स्थिति है कि जब कभी कोई जंगली पशु शेर या हाथी किसी आदमी को जान से मार देता है तो सरकार की तरफ से 5 लाख रुपये का compensation देने का प्रावधान है, लेकिन इसमें जितने भी लोग मारे गए हैं या घायल हुए हैं, बहुत सारे लोग अपंग भी हो गए हैं, उनको आज तक कोई compensation नहीं दिया गया है। बहुत से लोग मर गए हैं और कुछ लोग विकलांग होकर जी रहे हैं, जिसके कारण बहुत दिक्कत हो रही है।

महोदय, मुझे आपसे एक अन्य बात कहनी है कि जानवरों के खेत चरने से फसलों का जो नुकसान हो रहा है, कोई गाँव ऐसा बाकी नहीं है, जहां 12-12, 15-15 लाख रुपये के कांटे के तार न लगाए हों। इस नुकसान को सरकार ने अभी तक फसल बीमा के दायरे में नहीं लिया है। जब से यह पता लगा कि लोगों की 50 परसेंट से भी ज्यादा फसलें इन जानवरों के द्वारा चरी गई हैं, सभी जानवर पूरा ग्रुप बनाकर जाते हैं और जो वहां जाता है, उसके ऊपर हमला कर देते हैं और पूरी फसल चर जाते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

महोदय, मुझे आपसे एक बात और कहनी है कि हिन्दुस्तान में दूध का संकट है। जितनी खपत हो रही है, उतना उत्पादन नहीं है यानी कि लोगों को नकली दूध पीने को मिल रहा है। मैं इस सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि गोवंशी पशुओं के लिए एक सुनिश्चित और पॉजिटिव पॉलिसी बनाएं, जिससे